10 महिलाओं महिला प्रशासकों, कलाकारों, वैज्ञानिकों और समाज सुधारकों के नाम पर देश के विश्वविद्यालयों में चेयर की स्थापना की जाएगी। इन महिलाओं में हंसा मेहता और देवी अहिल्या बाई होल्कर शामिल हैं।

फिर किराया वृद्धि की भूमिका बना रहा रेलवे

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- भारत में अब भी पड़ोसी देशों के मुकाबले कम रेल किरायों का हो रहा प्रचार
- रेलवे के आधुनिकीकरण व विस्तार के लिए यात्रियों को और बोझ सहने का तर्क

प्रतीकात्मक।

पहली जनवरी को सभी दर्जों में हल्की किराया बढ़ोतरी के बाद भी रेलवे को चैन नहीं है। यात्री घाटे को पूरा करने के लिए वह अभी किराया बढ़ोतरी के प्रत्यक्ष और परोक्ष तरीके खोजने में जुटा है। इसे वाजिब ठहराने के लिए मंत्रालय की ओर से इन दिनों एक अभियान छेड़ा गया है। जनता को यह समझाने की कोशिश की जा रही है कि भारत में रेल किराया अब भी पड़ोसी देशों से काफी कम है। इसलिए थोड़ी और बढ़ोतरी हो जाए तो उसके लिए तैयार रहें। अतिरिक्त बोझ सहे बगैर यात्रियों को बेहतर सुविधाएं देने के लिए रेलवे का आधुनिकीकरण व विस्तार कठिन होगा।

इसके लिए मंत्रालय की ओर से कुछ अधिकारियों से लेख लिखवाए जा रहे हैं और मीडिया को उनकी प्रतियां बांटी जा रही हैं। साथ ही ग्राफिक्स के माध्यम से पाकिस्तान, बांग्लादेश और श्रीलंका की अपेक्षा भारत में रेल किरायों की स्थिति दर्शाने का प्रयास किया जा रहा है।

ऐसे ही एक ग्राफिक्स में दर्शाया गया है कि बांग्लादेश में उपनगरीय ट्रेनों का किराया प्रति किलोमीटर 33 पैसे, पाकिस्तान में 48 पैसे तथा श्रीलंका में 48.1 पैसे है, वहीं भारत में अब भी लोकल ट्रेनों में लोग मात्र 22.8 पैसे प्रति किलोमीटर के किराये पर सफर कर रहे हैं। इसी प्रकार लंबी दूरी की गैर-वातानुकूलित ट्रेनों का किराया पाकिस्तान में 48 पैसे, श्रीलंका में 67.9 पैसे और बांग्लादेश में 147 पैसे प्रति किलोमीटर है, वहीं भारत में यात्रियों को केवल 39.5 पैसे प्रति किलोमीटर देने पड़ते हैं। इसी प्रकार वातानुकूलित श्रेणियों के किरायों की भी तुलना दिखाई गई है। इसके मुताबिक एसी क्लास के लिए भारत में लोगों को केवल 175 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया देना पड़ रहा है। जबकि पाकिस्तान के लोग एसी दर्जे के लिए 176.5 पैसे तथा बांग्लादेश के लोग 227 पैसे प्रति किलोमीटर के हिसाब से किराया चुकाते हैं। कुल मिलाकर यह कहने की कोशिश की गई है भारत में अभी किराया वृद्धि की काफी संभावना है।

बजट से पहले मंत्रालय की इन गतिविधियों को जानकार एक और किराया बढ़ोतरी की भूमिका के रूप में ले रहे हैं। यह वृद्धि प्रत्यक्ष या परोक्ष किसी भी रूप में हो सकती है। सबसे ज्यादा संभावना उपनगरीय ट्रेनों का किराया बढ़ाए जाने की बताई जाती है, जिसे पहली जनवरी से लागू बढ़ोतरी में छोड़ दिया गया था। लेकिन, जिस तरह जनता ने उस बढ़ोतरी को आराम से स्वीकार कर लिया और किसी प्रकार के विरोधी स्वर कहीं सुनाई नहीं दिए, उसे देखते हुए अब इस सेगमेंट को भी छेड़ने की गुंजाइश बनाई जा रही है। परंतु चूंकि उपनगरीय किरायों का मुद्दा सामान्य मेल, एक्सप्रेस ट्रेनों के किरायों की तुलना में काफी संवेदनशील माना जाता है, इसलिए दूसरी संभावना परोक्ष बढ़ोतरी की हो सकती है। इसमें आरक्षण शुल्क, सुपर फास्ट शुल्क में बढ़ोतरी अथवा स्टेशन डेवलपमेंट सरचार्ज के रूप में एक नया शुल्क लगाए जाने की आशंका भी जताई जा रही है।

माना जाता है कि पहली जनवरी की किराया बढ़ोतरी रेलवे ने चालू वित्तीय वर्ष में अपने बेकाबू आपरेटिंग रेशियो को 100 फीसद से नीचे लाने के लिए की थी। जबकि, आगे होने वाली बढ़ोतरी से अगले वित्तीय वर्ष के यात्री घाटे को नियंत्रित किया जाएगा।

गृह मंत्री शाह की उपस्थिति में शांति समझौता करेंगे बोडो अलगाववादी

जागरण ब्यूरो, नई दिल्ली

- चार अलगाववादी गुटों के प्रतिनिधि और असम के मुख्यमंत्री करेंगे समझौते पर हस्ताक्षर
- एनडीएफबी ने अलग राज्य की मांग छोड़ी, दिए जा सकते हैं अधिक राजनीतिक व आर्थिक अधिकार

अमित शाह। फाइल

दशकों से हिंसा से जूझ रहे असम में स्थायी शांति की उम्मीदें बढ़ गई हैं। अलग बोडोलैंड की मांग करने वाले नेशनल डेमोक्रेटिक फेडरेशन ऑफ बोडोलैंड (एनडीएफबी) के चार गुटों ने हिंसा का रास्ता छोड़ने का फैसला किया है। इस सिलसिले में सोमवार को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की मौजूदगी में इन संगठनों के प्रतिनिधि और असम के मुख्यमंत्री सर्बानंद सोनोवाल समझौते पर हस्ताक्षर करेंगे।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार समझौते में अलग बोडोलैंड राज्य की मांग को नहीं माना गया है। लेकिन, बोडो लोगों को कुछ अधिक राजनीतिक अधिकार व आर्थिक पैकेज दिए जा सकते हैं।

गृह मंत्रालय के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि असम में स्थायी शांति के लिए बोडो समस्या के समाधान की कोशिश लंबे समय से जारी थी। इसी सिलसिले में गुरुवार को बोडो अलगाववादी गुटों के 644 कैडरों ने असम के मुख्यमंत्री के सामने आत्मसमर्पण किया था। इससे 15 दिन पहले म्यांमार में रह रहे एक गुट से जुड़े 50 कैडरों ने भारत आकर हथियारों के साथ आत्मसमर्पण कर दिया था। इससे इस समस्या के अंतिम समाधान की उम्मीद बढ़ गई थी।

उच्च पदस्थ सूत्रों के अनुसार, जिन चार गुटों के साथ सोमवार को समझौता होने वाला है, उनमें रंजन डैमारी, गोविंदा बासुमातरी, धीरेन बारो और बी साओरैगरा के नेतृत्व वाले गुट शामिल हैं। बी आओरैगरा ने 2015 में आइके सोंगबीजीत गुट की कमान संभाली थी।

आरोप है कि सोंगबीजीत ने दिसंबर 2014 में 70 आदिवासियों की हत्या का आदेश दिया था। इसके बाद उसे हटा दिया गया था। समझौते के तहत दो दिन पहले जेल में बंद डैमारी को रिहा किया गया था। ये चारों समझौते पर हस्ताक्षर के लिए दिल्ली आ रहे हैं। वैसे गृह मंत्रालय के अधिकारियों ने साफ कर दिया कि समझौते के कारण असम के राजनीतिक नक्शे पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि एनडीएफबी ने अलग राज्य की मांग छोड़ दी है।

जाहिर है बोडो क्षेत्रीय परिषद को कुछ अधिक राजनीतिक व आर्थिक स्वायतता का प्रावधान किया जा सकता है। असम के भीतर बोडो लोगों को अधिक अधिकार देने पर राज्य के दूसरे नागरिकों के साथ विचार-विमर्श के लिए एक आयोग का गठन भी किया जाएगा।

न्यूज गैलरी

सोशल मीडिया पर छाया देशभक्ति का रंग

नई दिल्ली : देश का 71वें गणतंत्र दिवस के मौके पर सोशल मीडिया भी देशभक्ति की भावनाओं से गुलजार है। गणतंत्र दिवस पर की जाने वाली पोस्ट में हिंदी का हिस्सा सर्वाधिक रहा है। पंद्रह भारतीय भाषाओं में सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म उपलब्ध कराने वाला शेयरचैट पर गणतंत्र दिवस के मौके पर दो लाख से भी ज्यादा पोस्ट को 15 करोड़ व्यूज मिले हैं। इन्हें 75 हजार से ज्यादा वाट्सएप शेयर प्राप्त हुए हैं। शेयरचैट कम्यूनिकेशन हेड राहुल नाग के मुताबिक, 23 जनवरी से 25 जनवरी को दोपहर साढ़े बारह बजे तक सबसे ज्यादा पोस्ट हिंदी में आई हैं। सभी भाषाओं में डाली गई पोस्ट में हिंदी का हिस्सा 50 फीसद है। (जाब्यू)

एसएसबी में भत्तों और बकाए का भुगतान रुका

नई दिल्ली : देश की सीमा की रक्षा करने वाले सशस्त्र सीमा बल (एसएसबी) के जवानों और अधिकारियों को बकाया धन और भत्तों का भुगतान जनवरी और फरवरी के लिए रोक दिया गया है। ऐसा धन की कमी के चलते किया गया है। सारी बकाया धनराशि मार्च में दी जाएगी। यह जानकारी संगठन की ओर से दी गई है। पता चला है कि अर्धसैनिक बल के मुख्यालय ने अपनी सभी शाखाओं को सूचित कर दिया है कि उसके पास जनवरी और फरवरी में सिर्फ वेतन भुगतान के लिए ही धन बचा है। (प्रेट्र)

नेपाल ने भारत-पाक के बीच मध्यस्थता की पेशकश की

प्रस्ताव ▶ कहा, साथ बैठने और विचार साझा करने से चीजें सुलझेंगी

दोनों देशों के बीच सीधा संवाद विकसित करने पर भी दिया बल

काठमांडू, प्रेट्र : भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव कम करने के लिए नेपाल ने शनिवार को कश्मीर और सीमापार आतंकवाद के मुद्दे पर मध्यस्थता की पेशकश की है। परमाणु शक्ति संपन्न दोनों पड़ोसियों के बीच मध्यस्थता की पेशकश करने वाला नेपाल पहला दक्षिण एशियाई देश है। नेपाल सरकार के एक सूत्र ने कहा कि आपसी विवाद को सुलझाने के लिए दोनों देशों के बीच बातचीत बहुत जरूरी है और इसी से दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन (सार्क) को भी नया जीवन मिलेगा।

सूत्र ने कहा, 'किसी भी समस्या के समाधान के लिए वार्ता सबसे बेहतर तरीका है। मतभेद हो सकते हैं लेकिन उन्हें बातचीत के जरिए ही सुलझाया जा सकता है। यदि जरूरी हो तो हम मध्यस्थ की भूमिका निभा सकते हैं।' उसने कहा कि मुद्दों को सुलझाने के लिए सबसे अच्छा तरीका दोनों देशों के बीच बेहतर संवाद कायम करना होगा। सूत्र ने कहा, 'हमारी भूमिका हो सकती है लेकिन (दोनों पक्षों के लिए) सीधा संवाद विकसित करना बेहतर होगा।'

पिछले साल अगस्त में जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 को खत्म किए जाने के बाद भारत और पाकिस्तान के बीच तनाव बढ़ा है। इस निर्णय के बाद पाकिस्तान ने भारत के साथ राजनयिक संबंध कम कर दिए थे और भारतीय राजनयिक को वापस भेज दिया था।

सूत्र ने कहा, 'जब हम साथ आएंगे, बैठेंगे और अपने विचार साझा करेंगे तब चीजें सुलझेंगी। हर स्थिति में हमें एक साथ बैठना होगा और समस्या को सुलझाना होगा, अन्यथा चीजें बिगड़ सकती हैं।'

सार्क में जान फूंकने की जरूरत : सार्क शिखर सम्मेलन को लेकर वर्तमान अनिश्चितता की स्थिति पर चिंता प्रकट करते हुए सूत्र ने कहा कि सार्क और आतंकवाद के बीच कोई संबध नहीं है। हम किसी भी तरह के आतंकवाद के खिलाफ हैं। दोनों मुद्दों को जोड़ा नहीं जाना चाहिए। इस संगठन में प्राण फूंकने की जरूरत है और गलतफहमी दूर की जानी चाहिए। सूत्र ने कहा, 'सार्क मृतप्राय नहीं है। यह जिंदा है। बस एक बात है कि हमारी बैठक नहीं हुई है। आशा है कि हम इसे पुनः जीवंत कर सकते हैं।'

2016 से नहीं हुआ सार्क शिखर सम्मेलन : पिछला सार्क सम्मेलन 2014 में काठमांडू में हुआ था जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने हिस्सा लिया था। 2016 में सार्क की बैठक इस्लामाबाद में होनी थी, लेकिन उड़ी में भारतीय सेना के कैंप पर आतंकी हमले के बाद भारत ने बैठक में शामिल होने से इन्कार कर दिया था। बाद में बांग्लादेश, भूटान और अफगानिस्तान के भी शामिल होने से मना करने पर शिखर सम्मेलन को रद कर दिया गया था। उसके बाद से यह बैठक नहीं हुई है।

ट्रंप भी कर चुके हैं मध्यस्थता की पेशकश

नेपाल से पहले अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने भी भारत और पाकिस्तान के बीच मध्यस्थता की कई बार पेशकश कर चुके हैं। लेकिन भारत का स्पष्ट कहना है कि कश्मीर पर किसी तीसरे पक्ष की मध्यस्थता उसे स्वीकार नहीं है। यह द्विपक्षीय मसला है। भारत पाकिस्तान के साथ बातचीत के लिए तैयार भी है, लेकिन शर्त यह है कि इस्लामाबाद पहले आतंकियों पर लगाम लगाए और क्षेत्र में शांतिपूर्ण माहौल बनाए।

सोनिया बोलीं, संविधान और उसके मूल्यों पर हो रहा हमला

नई दिल्ली, प्रेट्र : कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने शनिवार को लोगों से अपील की कि वे अपने व्यक्तिगत पूर्वाग्रहों से ऊपर उठकर संविधान और उसके मूल्यों की रक्षा के लिए एकजुट हों। सोनिया ने दावा किया कि संवैधानिक मूल्यों को एक गहरी साजिश के तहत निशाना बनाया जा रहा है। इसकी रक्षा के लिए सबको एकजुट होने की जरूरत है।

गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने कहा, 'यह हर नागरिक का दायित्व है कि वह देश के संविधान की रक्षा करने और देश की एकता को मजबूत करने की दिशा में कार्य करे। लोगों को धर्म, क्षेत्रवाद और भाषा के नाम पर बांटने की कोशिश की जा रही है। देश में अशांति, भय और असुरक्षा का एक अभूतपूर्व वातावरण तैयार कर दिया गया है। आम आदमी यह सोचने लगा है कि मौजूदा सरकार के हाथों में संवैधानिक मूल्य अब सुरक्षित नहीं रह गए हैं।'

कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी ने आरोप लगाया कि वर्तमान की केंद्र सरकार अपनी आर्थिक नाकामियों, प्रशासनिक विफलता, आसमान छूती महंगाई, हर तरफ मंदी के माहौल और बढ़ती बेरोजगारी से देश की जनता का ध्यान हटाने के लिए माहौल खराब करने का काम कर रही है। सोनिया गांधी ने कहा कि संविधान का हर अक्षर महज छपा हुआ एक शब्द भर नहीं है, बल्कि यह हर नागरिक के लिए जीता-जागता एक दर्शन है। हमें इसकी रक्षा करने के लिए साथ आने की जरूरत है।

राजपथ पर आज दिखेगी सैन्य ताकत व संस्कृति की झलक

- उपग्रह भेदी हथियार 'शक्ति', चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भव्य सैन्य परेड का होंगे हिस्सा

नई दिल्ली, प्रेट्र : देश के 71वें गणतंत्र दिवस समारोह में रविवार को राजपथ पर भारत की बढ़ती सैन्य ताकत, समृद्ध सांस्कृतिक विविधता और सामाजिक-आर्थिक प्रगति का भव्य प्रदर्शन होगा। गणतंत्र दिवस के लिए सुरक्षा के सख्त इंतजाम किए गए हैं। राजपथ पर आसमान से भी नजर रखी जाएगी। उपग्रह भेदी हथियार 'शक्ति', थलसेना का युद्धक टैंक भीष्म, पैदल सेना के युद्धक वाहन और हाल ही में भारतीय वायु सेना में शामिल किए गए चिनूक और अपाचे हेलीकॉप्टर भव्य सैन्य परेड का हिस्सा होंगे।

इसके अलावा के-9 वज्र और धनुष तोपें, चलित उपग्रह टर्मिनल और आकाश मिसाइल प्रणाली मैकेनाइज्ड दस्ते का मुख्य आकर्षण होंगे। राफेल और तेजस युद्धक विमान, हल्के लड़ाकू हेलीकॉप्टर, आकाश मिसाइल प्रणाली और अस्त्र मिसाइल के मॉडल प्रदर्शित किए जाएंगे। डोर्नियर विमान और सी-130 जे सुपर हरक्यूलीज विमान भी दिखाई देंगे। पांच जगुआर विमान और पांच मिग-29 विमान 'एरोहेड' फार्मेशन में वायुसेना के पराक्रम का प्रदर्शन करेंगे। परेड का समापन सुखोई-30 एमकेआई जेट विमानों के हवाई करतब से होगा।

पहले युद्ध स्मारक जाएंगे प्रधानमंत्री : गणतंत्र दिवस परेड समारोह की शुरुआत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडिया गेट के समीप स्थित राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर जाकर कृतज्ञ राष्ट्र की ओर से शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। यह पहली बार होगा जब प्रधानमंत्री अमर जवान ज्योति की बजाय राष्ट्रीय युद्ध स्मारक पर शहीदों को श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। परेड की शुरुआत राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद द्वारा परेड की सलामी लेने से होगी।

राज्य और केंद्र शासित प्रदेशों की 16 झांकियां : राजपथ पर राष्ट्र की बहुमूल्य सांस्कृतिक धरोहर और आर्थिक प्रगति को दर्शाने वाली 22 झांकियों में से 16 झांकियां राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों की होंगी और छह विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की होंगी। विभिन्न मंत्रालयों और विभागों की छह झांकियों में 'स्टार्ट अप इंडिया' और 'जल जीवन मिशन' जैसी सरकारी योजनाओं का प्रदर्शन किया जाएगा।

ले.जनरल असित मिस्त्री के हाथों में परेड की कमान : परेड कमांडर दिल्ली क्षेत्र के जनरल ऑफिसर कमांडिंग लेफ्टिनेंट जनरल असित मिस्त्री के हाथों में परेड की कमान होगी। परेड में पहला दस्ता सेना की 61वीं घुड़सवार टुकड़ी का होगा।

ब्राजील के राष्ट्रपति मुख्य अतिथि

गणतंत्र के मौके पर डेढ़ घंटे के समारोह में ब्राजील के राष्ट्रपति जायेर बोलसोनारो मुख्य अतिथि होंगे। वह दो दिन से भारत की यात्रा पर आए हुए हैं। लातिन अमेरिकी देश ब्राजील के साथ भारत के मधुर संबंध हैं।

बाल पोर्नोग्राफी तक पहुंच रोकने को एप की जरूरत

- राज्यसभा समिति ने बच्चों का यौन शोषण व सोशल मीडिया पर बाल पोर्नोग्राफी का प्रसारण रोकने के लिए रिपोर्ट सौंपी
- समिति ने 40 सिफारिशें की हैं, जिसमें यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम भी शामिल है

नई दिल्ली, प्रेट्र : बच्चों के यौन शोषण को रोकने और सोशल मीडिया पर बाल पोर्नोग्राफी की पहुंच और प्रसारण रोकने के लिए राज्यसभा की एक समिति ने 40 सिफारिशें की हैं। इनमें सभी उपकरणों पर निगरानी एप को अनिवार्य बनाना और यौन अपराधों से बच्चों का संरक्षण अधिनियम और सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम में संशोधन का सुझाव शामिल है।

इस समिति के प्रमुख और कांग्रेस सांसद जयराम रमेश ने उपराष्ट्रपति और राज्यसभा के सभापति एम वेंकैया नायडू को रिपोर्ट सौंपी। इसमें बाल पोर्नोग्राफी रोकने के लिए कई और सिफारिशें की गई हैं। इसके अलावा, ऐसे व्यापक सामाजिक सरोकार के मुद्दे पर जांच की खातिर समिति गठित करने के लिए नायडू की सराहना की गई है। रिपोर्ट में रमेश ने कहा कि यह एक अच्छा मॉडल है, जिसे समय-समय पर सामाजिक मुद्दों पर विचार करने के लिए किया जा सकता है।

बाल पोर्नोग्राफी की गंभीरता पर चिंता व्यक्त करते हुए समिति ने तकनीकी, संस्थागत, सामाजिक और शैक्षणिक उपाय करने की बात भी कही है। सोशल मीडिया पर पोर्नोग्राफी के खतरनाक मुद्दे और बच्चों और समाज पर इसके प्रभावों के बारे में राज्य-स्तरीय पहल का सुझाव दिया गया है। समिति ने रिपोर्ट में कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बाल पोर्नोग्राफी की समस्या पर संज्ञान लेते हुए 'मन की बात' कार्यक्रम में भी इस विषय को शामिल करना चाहिए। उन्हें बताना चाहिए कि इससे निपटने के लिए क्या उपाय किए जा सकते हैं।

समिति ने अनुरोध किया कि उन्होंने जैसे सौर ऊर्जा के क्षेत्र में अंतरराष्ट्रीय सौर गठबंधन का गठन किया है, वैसे ही इस समस्या से निपटने के लिए भी उन्हें 'वैश्विक राजनीतिक गठजोड़' बनाने की पहल करनी चाहिए।

'संस्थाओं के लिए नौकरशाही व राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति अहम'

नई दिल्ली, प्रेट्र : नोबेल पुरस्कार विजेता वैज्ञानिक वेंकटरमन रामकृष्णन ने शनिवार को कहा कि अच्छे संस्थानों के संचालन के लिए नौकरशाही और राजनीतिक हस्तक्षेप से मुक्ति बेहद अहम है। भारतीय मूल के ब्रिटिश अमेरिकी स्ट्रक्चरल बायोलॉजिस्ट रामकृष्णन अशोक यूनिवर्सिटी के स्कूल ऑफ बायोसाइंस के उद्घाटन अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा, 'अशोक यूनिवर्सिटी एक निजी यूनिवर्सिटी है और शुरुआत में मैं निजी यूनिवर्सिटी के विचार के खिलाफ कुछ-कुछ पूर्वाग्रह से ग्रसित था। लेकिन इसके कुछ पहलुओं से मैं प्रभावित था।'

यूनिवर्सिटी की सराहना करते हुए उन्होंने कहा कि यह योग्यता से संचालित है और उच्च मानकों को बरकरार रखा है। अशोक यूनिवर्सिटी का लिबरल आर्ट्स पर जोर वास्तव में अच्छा उदाहरण स्थापित कर सकता है। भारत में जन्मे रामकृष्णन को दो और वैज्ञानिकों के साथ संयुक्त रूप से कैमिस्ट्री का नोबेल पुरस्कार मिला था। उन्हें यह पुरस्कार राइबोसोम की संरचना और उसके कार्यों पर शोध के लिए मिला था।

'मतदान की अहमियत नहीं समझते हैं कुछ वोटर'

नई दिल्ली, प्रेट्र : राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने शनिवार को कहा कि कुछ मतदाता मतदान की अहमियत नहीं समझते हैं। राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर एक कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कोविंद ने कहा कि पहले आम चुनाव से लेकर पिछले साल हुए 17वें लोकसभा चुनाव तक मतदाताओं ने दुनियाभर में भारतीय लोकतंत्र की विश्वसनीयता बढ़ाई है। वह इसके लिए देश के सभी मतदाताओं को धन्यवाद देते हैं। लेकिन, आज की तारीख में भी कुछ मतदाता अपने मताधिकार की अहमियत नहीं समझते हैं। उन्हें जानना चाहिए कि दुनिया के कई लोकतांत्रिक देशों में आम लोगों को मताधिकार हासिल करने के लिए संघर्ष करना पड़ा था और कुर्बानी देनी पड़ी थी।

राष्ट्रपति ने कहा कि ब्रिटेन जैसे पुराने लोकतंत्र में भी महिलाओं को बीसवीं सदी में मताधिकार मिला। इसके लिए उन्हें तीन दशकों तक संघर्ष करना पड़ा। लेकिन, भारतीय संविधान निर्माताओं ने सभी वयस्क भारतीयों को यह महत्वपूर्ण अधिकार बिना किसी भेदभाव के दिया। कोविंद ने याद दिलाया कि आजादी के तत्काल बाद देश के सभी वयस्क नागरिकों को वोट डालने का अधिकार दिया गया था। उस समय इसकी बहुत आलोचना हुई थी, क्योंकि कुछ ही विकसित और समृद्ध देशों में लोकतांत्रिक व्यवस्था थी।

कहा गया था कि सिर्फ 16 फीसद साक्षरता और गरीबी के चलते सभी वयस्कों को मताधिकार की व्यवस्था सफल नहीं होगी। इस निर्णय को इतिहास का सबसे बड़ा जुआ करार दिया गया। लेकिन, हमारे मतदाताओं ने इसे विश्व इतिहास में लोकतंत्र का सबसे बड़ा सफल प्रयोग साबित किया। राष्ट्रपति ने स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से 17वें लोकसभा चुनाव के सफल आयोजन के लिए चुनाव आयोग द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों की सराहना की।

चुनाव प्रक्रिया को जीवंत बनाने के लिए आयोग का आभार : राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर शनिवार को लोगों को शुभकामनाएं देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि देश चुनावी प्रक्रिया को जीवंत और भागीदारीपूर्ण बनाने के प्रयासों के लिए चुनाव आयोग का आभार व्यक्त करता है। पिछले 10 वर्षों से चुनाव आयोग 25 जनवरी को राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में मना रहा है।

राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर शनिवार को राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने नई दिल्ली स्थित मानेकशॉ केंद्र में आयोजित कार्यक्रम में पहली बार मतदाता बने युवाओं को मतदाता पहचान पत्र सौंपा। यह दिवस साल 2011 से मनाया जा रहा है। प्रेट्र

कानूनी हथकंडा

सुप्रीम कोर्ट से दया याचिका खारिज होने की न्यायिक समीक्षा का किया अनुरोध, एक फरवरी को सुबह छह बजे होनी है निर्भया के गुनहगारों को फांसी

निर्भया के गुनहगार ने राष्ट्रपति के फैसले को दी चुनौती

नई दिल्ली, प्रेट्र : वर्ष 2012 में हुए निर्भया सामूहिक दुष्कर्म एवं हत्या मामले में मौत की सजा पाए दोषियों में से एक ने दया याचिका खारिज करने के राष्ट्रपति के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी है। शनिवार को याचिका दायर कर उसने दया याचिका खारिज किए जाने की न्यायिक समीक्षा का अनुरोध किया है।

दोषी मुकेश कुमार सिंह (32) की ओर से यह याचिका वकील वृंदा ग्रोवर ने दायर की है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने 17 जनवरी को उसकी दया याचिका खारिज कर दी थी। वृंदा ग्रोवर ने कहा, 'जिस तरह से दया याचिका खारिज की गई है, उसकी न्यायिक समीक्षा के लिए अर्जी अनुच्छेद 32 के तहत दायर की गई है।' उन्होंने कहा कि शत्रुघ्न चौहान प्रकरण में शीर्ष अदालत द्वारा निर्धारित मानकों का पालन नहीं किया जा रहा है। इन मानकों में ऐसे कैदी को आवश्यक दस्तावेज उपलब्ध कराने की अनिवार्यता भी शामिल है। चारों दोषियों को एक फरवरी सुबह छह बजे फांसी देने के लिए मृत्यु वारंट जारी किया गया है।

अक्षय की क्यूरेटिव याचिका भी हो गई है खारिज: मुकेश ने फांसी की सजा के खिलाफ क्यूरेटिव याचिका दायर की थी जिसे सुप्रीम कोट ने खारिज कर दिया था। इसके बाद मुकेश ने दया याचिका दायर की थी। सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में फांसी की सजा पाए अन्य दोषी अक्षय कुमार की क्यूरेटिव याचिका भी खारिज कर दी थी। दो अन्य दोषियों पवन गुप्ता (25) और विनय कुमार शर्मा ने अभी तक सुप्रीम कोर्ट में क्यूरेटिव याचिका दायर नहीं की है।

क्या थी घटना : साल 2012 में 16 और 17 दिसंबर की दरम्यानी रात को 23 वर्षीय पैरामेडिकल छात्रा से छह व्यक्तियों द्वारा चलती बस में सामूहिक दुष्कर्म एवं बेरहमी से हमला किया गया था और उसे बाद में दक्षिणी दिल्ली में बस से फेंक दिया गया था। उसे सिंगापुर के अस्पताल ले जाया गया था जहां उसकी उपचार के दौरान मौत हो गई थी।

फांसी को टलवाने का प्रयास नाकाम : निर्भया के गुनहगारों द्वारा फांसी को टलवाने की हर संभव कोशिश की जा रही है। इसी कड़ी में दोषियों की तरफ से दिल्ली की सत्र अदालत में याचिका दायर कर आरोप लगाया था कि जेल के अधिकारी वे दस्तवेज मुहैया नहीं करा रहे हैं जो दया तथा क्यूरेटिव याचिकाएं दायर करने के लिए जरूरी हैं। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने याचिका का निपटारा करते हुए कहा कि अर्जी पर आगे किसी दिशा-निर्देश की आवश्यकता नहीं है। दोषियों के वकील तिहाड़ जेल के अधिकारियों से संबंधित दस्तावेज, पेंटिंग और डायरी की तस्वीरें ले सकते हैं।

'फांसी टालने के लिए दायर की जा रहीं अर्जियां'

जागरण संवाददाता, नई दिल्ली

निर्भया मामले में दोषियों से जुड़े दस्तावेज उनके अधिवक्ता को अदालत में सौंप दिए गए। पटियाला हाउस अदालत के अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अजय कुमार जैन ने कहा कि अब दस्तावेज उपलब्ध कराने का आदेश देने की कोई जरूरत नहीं है। यह आदेश अदालत ने दोषियों की उस अर्जी का निपटारा कर दिया, जिसमें आरोप लगाया गया था तिहाड़ जेल प्रशासन दस्तावेज उपलब्ध नहीं करा रहा है। इसके चलते उन्हें अपनी याचिका दायर करने में देर हो रही है।

तिहाड़ जेल प्रशासन दोषी विनय द्वारा बनाई गई 10 पेंटिंग, स्केच, 10 पन्नों की दरिंदा शीर्षक की किताब और अन्य दस्तावेज लेकर अदालत पहुंचा। तिहाड़ की तरफ से लोक अभियोजक ने अदालत को बताया कि दोषियों के अधिवक्ता ने जो भी दस्तावेज मांगे, उन्हें उपलब्ध कराए गए। इस तरह की अर्जी दायर कर दोषी सिर्फ देर करने की तरकीबें अपना रहे हैं। यह पूरी प्रक्रिया कानून को हराने के लिए चल रही है। दोषी जिस-जिस जेल में रहे, वहां से उनसे संबंधित जो भी दस्तावेज सहेजे गए थे, वह सब दे दिए गए हैं।

कह के रहेंगे

माधव जोशी